THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) It is estimated that 7.75 million ha. of wasteland have been afforested till June, 1986.

(b) The total amount allocated including States' share till the year 1986-87 is Rs. 1594.56 crores, that of which it is estimated that Rs. 1215 crores have been spent till June, 1986.

दक्षिण भारत में संसद के अधिवेशन का आयोजन

965. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या संसदीय कार्य मंत्री 4 मई, 1984 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की एकता को ध्यान में रखते हुए छह महीने के लिए संसद का अधिवेशन दक्षिण भारत (बंगलौर) में आयोजित करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) अभी सरकार का दिल्ली से बाहर संसद के किसी सत्र के आयोजन का कोई विचार नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Failure of HAL to design combat Aircraft

966. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindustan Aeronautics Limited has failed to design a wholly Indian combat aircraft during the 30 years of its working;

(b) if so, the details of the projects regarding designing and manufacturing of combat aircraft taken up by Hindustan Aeronautics Limited; and

(c) by when a wholly Indian combat aircraft is likely to be produced by the Hindustan Aeronautics Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND DEFENCE SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) M/s Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) have indigenously designed and produced a combat aircraft, viz., HF-24 (Marut), which had been in service for more than 15 years. Presently HAL is a major participant in the project undertaken by the Aeronautical Development Agency for the design and development of a 'Light Combat Aircraft'.

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम

967. **श्री जगदंबी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का कार्यक्रम जो सभी मंत्रालयों, संस्थानों तथा विभागों को 31 मार्च, 1986 तक मिल जाना चाहिए था ताकि उसका कार्यान्वयन 13 अप्रैल, 1986 से आरम्भ किया जा सकता, जून के अन्त तक प्रकाशित किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा की संसदीय समिति का न तो अध्यक्ष है और न उपाध्यक्ष और न ही तीन समितियों में से दो में संयोजक ही है और न ही राजभाषा विभाग इस संबंध में कोई व्यवस्था ही कर रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि टाइपराइटरों जैसी सुविधाएं नहीं है और किसी भी मंत्रालय/विभाग में न तो पर्याप्त संख्या में हिन्दी के टकक है और न ही आशुलिपिक ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से स्थिति में सुधार करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का वार्षिक कार्यक्रम 1986-87 पहली अप्रैल, 1986 से लागू है जिसकी प्रतियां कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस तिथि तक नहीं छप सकीं । जून, 1986 के दूसरे सप्ताह में इसकी प्रतियां छप चुकी थीं और तत्काल ही मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को इसके वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ।

(ग) संसदीय राजभाषा समिति की उपसमिति के दो संयोजकों का निधन हो गया है । नए संयोजक तथा अध्यक्ष के चयन के बारे में कार्रवाई चल रही है ।

(घ) और (ङ) यद्यपि यांत्रिक सुविधाएं जैसे टाइपराइटर आदि वांछित संख्या में उपलब्ध कराना संबंधित मंत्रालयों/विभागों की जिम्मेदारी है तथापि राजभाषा विभाग इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है । टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है ताकि मंत्रालयों/विभागों में इनकी कमी न रहे ।

Completion of behind the schedule Central Projects

968. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the number of Central Projects which are behind schedule in implementation by one to five years, giving details of each Project, State-wise;

(b) what are the details of efforts made to complete these projects without delay; and

(c) whether any improvement has been noticed as a result of such efforts?

THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) Of the projects costing Rs. 20 crore or more monitored by the Ministry, there are 74 Central Projects which have been delayed between 1 and 5 years. State-wise/Sector-wise details are given in the enclosed statement. [See Appendix CXXXIX. Annexure No. 54]

(b) and (c) The following efforts are being made to complete the projects without any further delay should create awareness of the need to complete Projects in time.

(i) Preparation of realistic project implementation plans.

(ii) Effective monitoring through Monthly Flash Report and Quarterly Status Report Monitoring Systems.

(iii) Constant pressure on project authorities for expeditious completion.

(iv) Inter-Ministerial coordination and inter-action.

(v) Close follow-up by concerned Ministries and project authorities with State Governments, equipment suppliers Consultants and other concerned agencies to minimise delays.

Robberies and dacoities in Delhi

969. SHRI KALPNATH RAI:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of robberies and dacoities which took place in Delhi during the last three months;

(b) the loss to human life and property which resulted from them; and

(c) what steps are being taken to improve the law and order situation in the capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The number of robberies and dacoities which took place during the last three